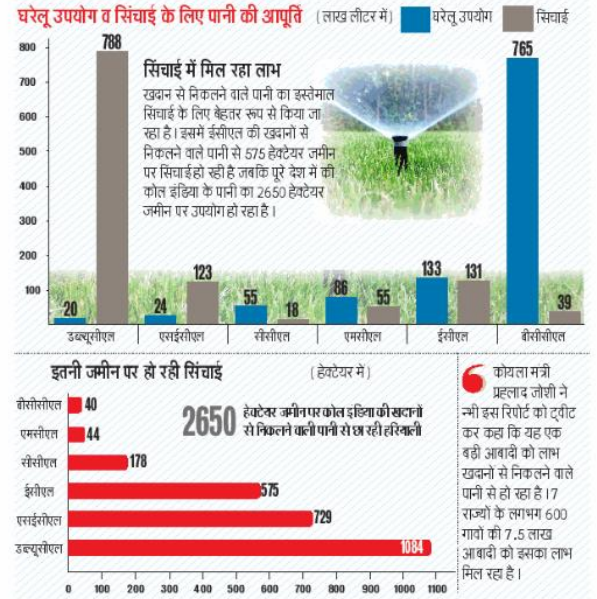
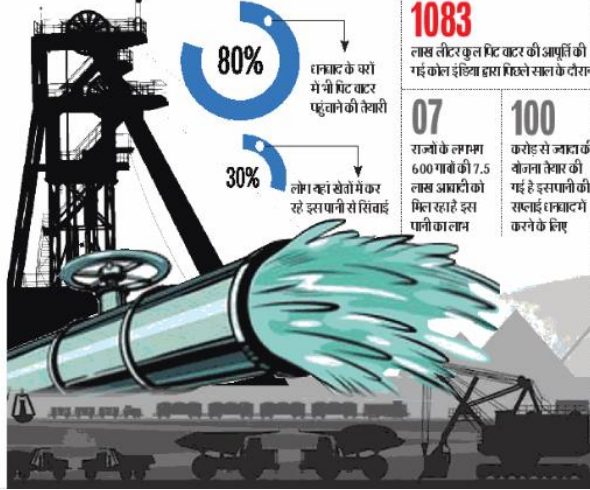


Date: 19-08-20
Publication: Dainik Jagran
Edition: Dhanbad

कोल इंडिया की खदानों के पानी से 7.5 लाख लोग हो रहे हैं लाभान्वित

आशीष अंबाड • धनबाद

कोयला खदानों से निकलनेवाली पानी को शुद्ध कर स्थानीय लोगों को घरेलू इस्तेमाल एवं सिंचाई के लिए उपलब्ध कराने की पहल कोल इंडिया ने शुरू की है। कोयला मंत्रालय को भेजी गई रिपोर्ट में इसका उल्लेख किया गया है। 2019-20 में कोल इंडिया की ईसीएल, बीसीसीएल, सीसीएल सहित छह कंपनी के पीट वाटर से लोग लाभान्वित हुए। इनमें 1083 लाख लीटर पानी प्रत्येक दिन घरेलू उपयोग में खर्च हो रहा है तो 1154 लाख लीटर पानी सिंचाई के लिए सप्लाई किया जा रहा है। देश के 7 राज्यों के लगभग 600 गांवों की 7.5 लाख आबादी को इसका लाभ मिल रहा है। झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, महाराष्ट्र सहित कई राज्यों जो जल संकट का सामना कर रहे हैं, वहां के लिए यह सौगात है। ईसीएल कुमारघुडी में भी पीट वाटर सप्लाई के लिए रॉ वाटर फिल्टर प्लांट लगाया गया।



Date: 20-08-20
Publication: Nai Duniya
Edition: Korba

आगमन

गेवरा, दीपका खदान का आज लेंगे जायजा

पॉजिटिव ग्रोथ की संभावनाएं तलाशेंगे सीआईएल के चेयरमैन

कोरबा। नईदुनिया प्रतिनिधि कोल इंडिया के चेयरमैन प्रमोद अग्रवाल (आईएस) गुरुवार से दो दिवसीय प्रवास पर कोरबा आ रहे हैं। इस दौरान गेवरा, दीपका व कुसमुंडा खदान का निरीक्षण के साथ ही सभी क्षेत्रीय महाप्रबंधक के साथ वर्चुअल मीटिंग कर उत्पादन की समीक्षा करेंगे। सभी कंपनियों के सीएमडी स्तर की वर्चुअल मीटिंग में उत्पादन व डिस्पैच पर विगत दिनों चर्चा हुई, इसमें सभी कंपनियों की रिपोर्ट निगेटिव आई थी। यही वजह है कि कोल इंडिया चेयरमैन खदानों का दौरा कर रहे हैं।

सीआईएल का चेयरमैन पद संभालने के बाद प्रमोद अग्रवाल का पहली बार प्रवास हो रहा है। प्रोटोकाल के मुताबिक अग्रवाल बुधवार की रात फ्लाईट से रायपुर पहुंचे और विश्राम किया। गुरुवार को सुबह आठ बजे



प्रमोद अग्रवाल

रायपुर से सड़क मार्ग से रवाना होंगे और 10.15 बजे विलासपुर भवन पहुंचेंगे। अल्प विश्राम के बाद गेवरा के लिए रवाना होंगे। दोपहर 12 बजे गेवरा हाउस पहुंचेंगे। अधिकारियों से मुलाकात के बाद सीधे खदान का निरीक्षण करने चले जाएंगे। दोपहर 2.15 से 3.30 बजे का वक्त भोजन के लिए आरक्षित रखा गया है। इसके बाद दीपका खदान जाएंगे और पांच बजे वापस लौटेंगे। अल्प

राज्य पावर प्लांट को पहले मिले कोयला: पांडेय

विद्युत उत्पादन के पावर प्लांट में कोयला की कमी व गुणवत्ता का मुद्दा अभिन्नता संघ के पदाधिकारी चेयरमैन के समक्ष रखेंगे। प्रांतीय अध्यक्ष राजेश पांडेय ने बताया कि हंसदेव ताप विद्युत गृह व मड़वा प्लांट में कोयला आपूर्ति नहीं हो रही है। इससे दोनों संयंत्र के समक्ष मात्र एक सप्ताह का कोयला शेष है। खदान

से कोयला लगातार खराब आ रहा है, इसका असर प्लांट संचालन पर हो रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य विद्युत कंपनी को प्राथमिकता के आधार पर कोयला एसईसीएल को सप्लाई करना चाहिए, पर ऐसा नहीं हो पा रहा है। चेयरमैन के समक्ष गुणवत्तायुक्त कोयला करने प्रस्ताव रखा जाएगा।

विश्राम के बाद रात आठ बजे तक सभी एरिया के महाप्रबंधक के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से चर्चा करेंगे। हालांकि इस दौरान कोरबा जिले के अधिकारी बैठक में उपस्थित रहेंगे। रात्रि विश्राम के बाद 21 अगस्त को सुबह नौ बजे कुसमुंडा खदान का निरीक्षण कर कुसमुंडा भवन में अधिकारियों के साथ चर्चा कर वापस विलासपुर के लिए रवाना हो जाएंगे। विलासपुर में भोजन

के साथ ही मुख्यालय अधिकारियों की बैठक लेकर रायपुर के लिए रवाना होंगे। उनके साथ एसईसीएल के सीएमडी एपी पंडा, निवेशक तकनीक आरपी निगम, मनोज कुमार समेत अन्य आला अप्रसर भी रहेंगे। कोयला उत्पादन के साथ ही डिस्पैच बढ़ाने पर लगातार दबाव बना हुआ। कोल प्रबंधन को नजर एसईसीएल की गेवरा, दीपका व कुसमुंडा खदान पर टिकी हुई है।

कोल इंडिया चैयरमैन ने दिए खुली खदानों में उत्पादन बढ़ाने के निर्देश

हरिभूमि न्यूज 18 कोरबा

कोल इंडिया के चैयरमैन प्रमोद अग्रवाल (आईएएस) गुरुवार को कोरबा प्रवास पर थे। इस दौरान चैयरमैन श्री अग्रवाल ने गेवरा, दीपका व कुसमुण्डा खदान का निरीक्षण कर उत्पादन व डिस्पैच

खास बातें

- गेवरा, दीपका, कुसमुण्डा खुली खदान का विद्या निरीक्षण उत्पादन-डिस्पैच बढ़ाने का
- सभी क्षेत्रीय महाप्रबंधकों के साथ वरुअल मीटिंग कर की समीक्षा

संबंधी जानकारी एकत्र की और अधिकारियों को उत्पादन व डिस्पैच बढ़ाने संबंधी निर्देश दिए। इसके बाद चैयरमैन श्री अग्रवाल ने सभी क्षेत्रीय महाप्रबंधक के साथ वरुअल मीटिंग कर कोबला उत्पादन की समीक्षा की। हालांकि इस दौरान गेवरा, दीपका, कुसमुण्डा, कोरबा और रायगढ़ के महाप्रबंधक उपस्थित थे।

सीआईएल चैयरमैन का पद संभालने के बाद प्रमोद अग्रवाल पहली बार कोरबा पहुंचे। गेवरा हाउस में भोजन के बाद दोपहर 3 बजे श्री अग्रवाल का काफिला



खदान का निरीक्षण करते कोल इंडिया के चैयरमैन श्री अग्रवाल।



अधिकारियों को दिशा निर्देश देते चैयरमैन।

गेवरा खदान पहुंचा जहाँ उन्होंने खदान का गहनता से निरीक्षण कर उत्पादन व डिस्पैच संबंधी जानकारी ली। इसके बाद 4 बजे श्री अग्रवाल दीपका खदान पहुंचे। यहाँ उन्होंने व्यू पॉइंट से खदान का निरीक्षण किया। इस दौरान श्री अग्रवाल ने साइलो और कोल सेल के अलावा एनटीपीसी कोल डिस्पैच का भी जायजा लिया। निरीक्षण के बाद श्री अग्रवाल ने अधिकारियों को कोल उत्पादन व डिस्पैच बढ़ाने संबंधी निर्देश दिए। शाम 5 बजे चैयरमैन श्री अग्रवाल कुसमुण्डा खदान के लिए रवाना हुए। 12 फर

कोल इंडिया ...

कुसमुण्डा जीएस कार्यालय में कुछ देर रुकने के बाद श्री अग्रवाल कुसमुण्डा खदान पहुंचे यहाँ भी उन्होंने खदान का निरीक्षण कर कोल उत्पादन व डिस्पैच संबंधी जानकारी ली। शाम 6 बजे के बाद चैयरमैन श्री अग्रवाल वापस गेवरा के लिए रवाना हुए। जहाँ शाम लगभग 6.30 बजे चैयरमैन श्री अग्रवाल ने संयुक्त सलाहकार समिति में शामिल श्रमिक नेताओं के साथ चर्चा की। इसके बाद गेवरा हाउस में श्री अग्रवाल ने सभी क्षेत्रीय महाप्रबंधकों के साथ वरुअल मीटिंग कर उत्पादन की समीक्षा की। हालांकि इस दौरान दीपका महाप्रबंधक टी के चंद्रशेखर, कोरबा के महाप्रबंधक एसके सिंह, गेवरा के महाप्रबंधक एसके पाल व कुसमुण्डा महाप्रबंधक पी रंजन शर्मा के अलावा रायगढ़ के महाप्रबंधक उपस्थित थे। वरुअल मीटिंग के दौरान जिले के अधिकारियों के अलावा कोलमा जेलरके सोहनपुर के महाप्रबंधकों से भी चैयरमैन ने उत्पादन व डिस्पैच बढ़ाने को लेकर दिशा निर्देश दिए हैं। दरअसल कुछ दिनों पूर्व कोल इंडिया के सभी क्षेत्रीय कंपनियों के सीएसडी स्तर के वरुअल मीटिंग में उत्पादन व डिस्पैच पर चर्चा हुई थी। इस दौरान सभी कंपनियों की रिपोर्ट विमर्शित हुई थी। यही वजह है कि कोल इंडिया चैयरमैन श्री अग्रवाल ने कोरबा उत्पादन के साथ ही डिस्पैच बढ़ाने का तत्काल ध्यान बना हुआ है। यही कोल प्रबंधन की नजर एसडीसीएल की गेवरा, दीपका और कुसमुण्डा खदान पर टिकी हुई है। सूत्रों की मानें तो गेवरा हाउस में आयोजित वरुअल मीटिंग के बाद देर रात चैयरमैन श्री अग्रवाल बिलासपुर के लिए रवाना हो जाएंगे। 21

अगस्त को चैयरमैन श्री अग्रवाल बिलासपुर मुख्यालय में अधिकारियों की बैठक लेकर रायपुर जाएंगे जहाँ से वे वापस कोलकाता रवाना हो जाएंगे। चैयरमैन श्री अग्रवाल के साथ एसडीसीएल के सीएसडी एपी पंडा, बिदेसक लक्ष्मीक और पी किशन, मनीष कुमार सहित अन्य आग अतिथि भी उपस्थित थे। ब्रिफक जगहन ने सभी 7 क्षेत्रीय मंत्र पत्र- कोल इंडिया के चैयरमैन प्रमोद अग्रवाल ने गेवरा हाउस में संयुक्त सलाहकार समिति के सदस्यों से चर्चा की। इस दौरान समिति के सदस्यों ने चैयरमैन श्री अग्रवाल को 7 क्षेत्रीय मंत्र पत्र सौंपा। जिसमें मुख्य रूप से कार्बनिलिंग माइनिंग वापस लिया जाए, गेवरा मुख्य मार्ग को बिलासपुर मुख्यालय से जोड़ा जाए, अस्पाताल में विशेषज्ञ चिकित्सकों की नियुक्ति के अलावा अन्य चिकित्सकीय सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं, कोल कर्मियों के वेल्फेयर की राशि मार्च 2018 की जगह अधिकारियों की तरह की 1 जनवरी 2017 से लागू किया जाए, सेंट्रल वर्कशॉप में कार्बन कर्मियों को रजिस्ट्रेशन अवकाश दिवस जाए, कोरबा काल में भी हमने टारगेट पूरा किया इसलिए स्पेशल पैकेज बॉना (50 लाख) दिया जाए, गेवरा से एसडीसीएल मुख्यालय और चापा के लिए बस सुविधा उपलब्ध कराई जाए, बैठक में एक्स्प्रेस के केंद्रीय अध्यक्ष रेशमलाल वादव, क्षेत्रीय महामंत्री महेश्वर वैष्णव, एटक के अध्यक्ष दीपक उपाध्याय, सचिव एलबी अग्रिया, वीकेएसएस के अध्यक्ष अलग सिंह, सचिव सीकराम साहू, सीट के अध्यक्ष विमल सिंह, सचिव जनरल कर्मा, इटक के अध्यक्ष वैष्णव किशोर, सचिव लोकल जयवर्धन सिंह जिले के चारों परिक्षेत्र के अधिकारी उपस्थित थे।

Date: 21-08-20
Publication: Dainik Bhaskar
Edition: Korba

खदानों का उत्पादन बढ़ाने के लिए नई मशीन और डंपर का लोकार्पण



हरी झंडी दिखाकर मशीन का लोकार्पण करते चेयरमैन

कोरबा- गेवरा। कोल इंडिया चेयरमैन प्रमोद अग्रवाल ने सोमवार को जिले क्षेत्र की तीन प्रमुख खदान गेवरा दीपका व कुसमुण्डा का निरीक्षण किया। शाम को 5 बजे चेयरमैन प्रमोद अग्रवाल कुसमुण्डा खदान पहुंचे। कोल फेस भी गए और उत्पादन को बढ़ाने तैयार 5

नई मशीनों का भी उद्घाटन किया। इसी तरह गेवरा खदान में भी दो 150 टन के दो डंपर का लोकार्पण किया गया। आज दो डंपर का लोकार्पण कोल इंडिया चेयरमैन प्रमोद अग्रवाल ने गुरुवार को किया है। यह मशीनें शुक्रवार फर्स्ट शिफ्ट से खदान में प्रोडक्शन में रहेंगे।

Date: 21-08-20
Publication: Nai Duniya
Edition: Raigarh

कोयला उत्पादन में एसईसीएल की बड़ी जिम्मेदारी : अग्रवाल

कोरबा(नईदुनिया प्रतिनिधि)। कोल इंडिया के चेयरमैन प्रमोद अग्रवाल ने कहा कि देश की कोयला आवश्यकताओं को पूर्ण करना हमारा दायित्व ही नहीं, बल्कि कर्तव्य भी है। कोल इंडिया के कुल उत्पादन में से लगभग एक चौथाई कोयला उत्पादन साउथ-ईस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड (एसईसीएल) द्वारा किया जाता है, इसलिए एसईसीएल पर बड़ी जिम्मेदारी है। गेवरा, दीपका और कुसमुंडा तीनों खुली खदानें एसईसीएल के मेगा प्रोजेक्ट हैं। कोयला उत्पादन में इन तीनों क्षेत्रों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है।

वरअसल, कोल इंडिया के चेयरमैन गुरुवार को एसईसीएल के दौरे पर गेवरा क्षेत्र पहुंचे। यहां उन्होंने गेवरा खुली

खदान का निरीक्षण किया और खनन कार्य का जायजा लिया। गेवरा खुली खदान के विस्तार के बारे में जानकारी ली और विस्तार की प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए। चेयरमैन ने अधिकारियों को स्पष्ट संकेत दिए कि कोयला उत्पादन में तेजी से बढ़ोतरी की जाए, ताकि देश की कोयला आवश्यकताओं को पूर्ण किया जा सके। उन्होंने एसईसीएल दीपका व कुसमुंडा खुली खदान का भी निरीक्षण किया तथा भविष्य की योजनाओं के बारे में जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने उत्पादन-उत्पादकता को बढ़ाने संबंधी आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। माइन निरीक्षण के दौरान उन्होंने उत्पादन बढ़ाने के साथ-साथ शून्य दुर्घटना के लक्ष्य को हासिल करने पर भी जोर दिया।

Date: 22-08-20
Publication: Business Standard
Edition: Ahmedabad
Entity: Ministry of Coal, Coal India Limited

Ministry okays 100% supply by Coal India to power units

SHREYA JAI
New Delhi, 21 August

Given the excessive coal stock available with Coal India (CIL), the ministry of coal has approved the company's plan to supply 100 per cent of the normative requirement to thermal power units.

The ministry has recommended increasing the 'annual contracted quantity' (ACQ) of coal to 100 per cent of the normative requirement of a non-coastal plant. It was 90 per cent earlier. For coastal plants, the ACQ has been increased to 70 per cent.

Normative requirement is the coal demand of a thermal power station based on its capacity, heat rate, boiler specifications and subsequent coal usage. Normative requirements are different for every station.

The decision of the coal ministry pertains to coal supply both under long-term agreement signed with CIL and coal supply linkage via the auction route.

CIL periodically holds auction of coal for the power and non-power sectors for short-term and medium-term coal supply contracts.

"In view of the request by CIL and recommendations of the ministry of power, the standing linkage committee (of the ministry of coal) recommended to increase the ACQ up to 100 per cent of the normative requirement," said the minutes of the meeting held this week.

The committee further said in case coal supply linkages are obtained through auction, the entitled quantity will be revised based on the new norms. Consumers will have to participate in

auctions to obtain linkages for the increased entitlements of ACQ.

In the above mentioned meeting, the national miner said it has sufficient stock of coal and there is slugging demand from the non-regulated sector (such as iron and steel, among others) due to Covid-19.

"CIL has decided to enhance the ACQ up to 100 per cent. This dispensation would be allowed to interested power plants on an optional basis. They will have to undertake that they would reduce import to the extent of increase in the ACQ," said the company.

This is in line with the recent Centre's directive to

reduce coal import. Last month, CIL launched a special category e-auction of coal for those companies and traders which import coal to meet their requirements.

The company also informed the ministry that around 700 million tonnes of coal would be available with CIL in the current financial year. It further said that production from next financial year will be in accordance with the plans to achieve the 1 billion tonne coal production target by 2024.

"Further, the impact of enhancement of ACQ would be that around 15 million tonne more coal would be committed to power producers. It was stated that CIL has waived off the levy of performance incentive (PI) for the first two quarters of 2020-21. This would also enable it to implement the coal import substitution as coal quantities above the ACQ level can be supplied without charging additional cost in the form of PI," CIL said.

CIL periodically holds auction of coal for the power and non-power sectors for short-term and medium-term coal supply contracts

नेट जीरो एनर्जी कंपनी की दिशा में कोल इंडिया

जागरण विशेष



आशीष अंबष्ट • धनबाद

कोल इंडिया लिमिटेड ने नेट जीरो एनर्जी की दिशा में कदमताल तेज कर दी है। वित्तीय वर्ष 2023-24 तक इसे नेट जीरो एनर्जी कंपनी बना लिया जाएगा। कोल इंडिया ने सभी कोयला कंपनियों को इसके लिए गाइडलाइन जारी की है। कंपनी और उसकी इकाइयों को अपने वहां उपयोग होने वाली सारी बिजली सौर ऊर्जा के माध्यम से बनानी है। योजना बन चुकी है। कोल इंडिया चेयरमैन प्रमोद अग्रवाल इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं।

कोल इंडिया व इसकी इकाइयों की जमीन पर सोलर प्लांट स्थापित हो सकते हैं। जो प्लान बना है उसमें कोल इंडिया मुख्यालय द्वारा अपनी वार्षिक ऊर्जा की आवश्यकता को पूरा करने को सौर ऊर्जा से 3,000 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा। चालू वित्तीय वर्ष में 12 मेगावाट उत्पादन का लक्ष्य है। वर्ष 2021-22 में 285, वर्ष 2022-23 में 1500

सौर ऊर्जा का सदुपयोग

- कोल इंडिया की खाली जमीन पर स्थापित होंगे सोलर प्लांट, तैयारी तेज
- 15 हजार करोड़ का बजट, कार्यालय की छतों पर लग रहा सोलर पैनल



कोल इंडिया की इकाई ईसीएल में सोलर पैनल से बिजली उत्पादन की दिशा में काम हो रहा है। सतग्राम एरिया में 40 एकड़ जमीन पर सोलर पैनल लगाया जाएगा।

जैगी गुप्ता, तकनीकी निदेशक, ईसीएल (प्लानिंग)

कोयला मंत्री योजना पर गंभीर

कोयला मंत्री ने हाल में ट्वीट कर सौर ऊर्जा के सदुपयोग के लिए गंभीरता दिखाई है। कहा है कि 2023-24 तक कोल इंडिया मुख्यालय नेट जीरो कंपनी बनेगा। 3000 मेगावाट ऊर्जा का लक्ष्य हासिल कर लिया जाएगा।

तथा 2023-24 तक 3000 मेगावाट बिजली का सौर ऊर्जा से उत्पादन होगा। सूत्रों का कहना है कि 15 हजार करोड़ का बजट है।



सीएमपीडीआईएल व कोल इंडिया मुख्यालय में हो रहा सदुपयोग

कोल इंडिया मुख्यालय कोलकाता, सीएमपीडीआईएल, धनबाद, आसनसोल व रांची मुख्यालय को मिलाकर करीब 125 किलोवाट से अधिक पावर जेनरेट करने के प्लांट लगे हैं। एमसीएल में भी सौर ऊर्जा से बिजली बनाई जा रही है। धनबाद में कोयला भवन की छत पर पांच साल पहले ही सोलर एनर्जी प्लांट लगाने की योजना थी। हालांकि उस पर काम अब तक शुरू नहीं हुआ। सीएमपीडीआईएल भवन में इसका प्रयोग सफल रहा है।

इसमें एनएलसी के साथ संयुक्त साझेदारी है। कार्यालय की छतों पर सोलर पैनल लगाने का काम निविदा से पूरा हो रहा है।

सौर ऊर्जा से बिजली उत्पादन की दिशा में कोल इंडिया बढ़ी आगे

सतग्राम एरिया में 40 एकड़ जमीन पर लगाया जाएगा सोलर पैनल

जितेंद्र मिश्रा

सांकतोड़िया : कोल इंडिया की इकाई ईसीएल में सोलर पैनल से बिजली उत्पादन की दिशा में काम हो रहा है। इसके लिए सतग्राम एरिया में 40 एकड़ जमीन पर सोलर पैनल लगाया जाएगा। ईसीएल सूत्रों ने बताया कि कोल इंडिया लिमिटेड प्रबंधन ने नेट जीरो एनर्जी की दिशा में कदमताल तेज कर दिया है। वित्तीय वर्ष 2023-24 तक इसे नेट जीरो एनर्जी कंपनी बना लिया जाएगा। कोल इंडिया ने सभी कोयला कंपनियों को इसके लिए गाइड लाइन जारी की है। कंपनी और उसकी इकाइयों को अपने यहां उपयोग होने वाली सारी बिजली सौर ऊर्जा के माध्यम से बनानी है ताकि पर्यावरण की रक्षा हो। कार्बन का उत्सर्जन न हो। इसके लिए योजना



बन चुकी है। कोल इंडिया चेयरमैन प्रमोद अग्रवाल इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। कोल इंडिया व इसकी इकाइयों के पास काफी जमीन है। इन पर सोलर प्लांट स्थापित हो सकते हैं। कोयला मंत्रालय भी इस योजना पर गंभीर है। वहीं जो प्लान बना है, उसमें कोल इंडिया मुख्यालय द्वारा अपनी वार्षिक ऊर्जा की आवश्यकता को पूरा करने के

लिए सौर ऊर्जा के माध्यम से 3,000 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाएगा। चालू वित्तीय वर्ष में 12 मेगावाट उत्पादन का लक्ष्य है। वर्ष 2021-22 में 285, वर्ष 2022-23 में 1500 तथा 2023-24 तक 3000 मेगावाट बिजली का सौर ऊर्जा से उत्पादन होगा। कोल इंडिया सूत्रों का कहना है कि इसके लिए 15 हजार करोड़ का बजट बना है। इसमें एनएलसी के साथ संयुक्त साझेदारी है। कार्यालय की छतों पर सोलर पैनल लगाने का काम निविदा से पूरा हो रहा

है। कोल इंडिया मुख्यालय कोलकाता, सीएमपीडीआईएल, धनबाद, आसनसोल व रांची मुख्यालय को मिलाकर करीब 125 किलोवाट से अधिक पावर जेनरेट करने के प्लांट लगे हैं। एमसीएल में भी सौर ऊर्जा से बिजली बनाई जा रही है। धनबाद में कोयला भवन की छत पर पांच साल पहले ही सोलर एनर्जी प्लांट लगाने की योजना थी। हालांकि उस पर काम अब तक शुरू नहीं हुआ। सीएमपीडीआईएल भवन में इसका प्रयोग सफल रहा है। ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड ने कार्यालयों की छत पर सोलर पैनल लगाने का काम शुरू कर दिया है। कोयला मंत्री ने योजना पर गंभीर रूप से हाल में ट्वीट कर सौर ऊर्जा के सदुपयोग के लिए गंभीरता दिखाई है। कहा है कि 2023-24 तक कोल इंडिया मुख्यालय नेट जीरो कंपनी बनेगा। 3000 मेगावाट ऊर्जा का लक्ष्य हासिल कर लिया जाएगा।

कोरोना से लड़ाई में मददगार बना सीएसआर बजट

धनबाद | विशेष संवाददाता

कोल इंडिया की लगभग सभी अनुषंगी कंपनियों में सीएसआर बजट की पूरी राशि खर्च नहीं हो पाती है। इस बात की पुष्टि कोल इंडिया की हर साल की वार्षिक रिपोर्ट से होती है।

यही सीएसआर फंड कोरोना से जान बचा रहा है। चालू वित्तीय वर्ष में सीएसआर बजट के भरोसे ही कोयला कंपनियों को कोरोना से लड़ाई लड़ रही हैं। कोयला बहुत हर राज्य में कोल कंपनियां कोरोना से जंग में मददगार साबित हो रही हैं। कोविड अस्पताल से लेकर कई तरह

का सहयोग कोयला कंपनियों की ओर से की जा रही हैं। बीसीसीएल के दो अस्पतालों सेंट्रल अस्पताल एवं भूली रिजनल अस्पताल में लगभग आठ सौ कोरोना मरीजों का इलाज हुआ है। इसके अतिरिक्त पुलिस प्रशासन को सीएसआर फंड से लगभग चार करोड़ की राशि प्रदान की गई है। निगम को 12.5 एमटी ब्लॉकिंग पाउडर उपलब्ध कराया गया है। कोल इंडिया और अनुषंगिक कंपनियों को 2019-20 में सीएसआर बजट 888.86 करोड़ मिला था, जिसमें खर्च केवल 194.79 करोड़ रुपए हुए थे।

सीएसआर बजट नहीं खर्च पाई कंपनियां

कंपनी	बजट	खर्च
ईसीएल	17.86	5.29
बीसीसीएल	27.73	1.00
सीसीसीएल	89.94	6.07
डब्ल्यूसीएल	10.64	4.50
एसईसीएल	158.76	24.93
एमसीएल	156.50	70.70
एनसीएल	130.02	24.54
सीएमपीडीआई	3.27	0.76
कोल इंडिया	294.04	57.00
कुल	888.86	194.79

पूर्व के सालों में भी यही हाल

2018-19 में सीआईएल और अनुषंगिक कंपनियों द्वारा 750.84 करोड़ के आबंटन के मुकाबले 416.47 करोड़ रुपए खर्च किए जा सके। इसी तरह 2017-18 में 622.15 करोड़ का बजट मिला। खर्च 483.78 करोड़ रुपए हुए। 2016-17 में 557.27 करोड़ रुपए का आवंटन हुआ। इस वर्ष सीएसआर में 489.67 करोड़ रुपए खर्च किए गए।